

कदन्न (Millets)

कदन्न (MILLETS)

कदन्न/ मिलेट्स/ मोटा अनाज:

- छोटे-बीज वाली फसलों को मिलेट्स के रूप में जाना जाता है
- अक्सर इन्हें 'सुपरफूड' के रूप में भी जाना जाता है
- इन अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए और ये भोजन के लिये उगाए गए पहले पौधों में से थे।

जलवायु संबंधी स्थिति:

- भारत में मुख्य रूप से खरीफ की फसल
- तापमान: 27°C-32°C
- वर्षा: लगभग 50-100 सेमी
- मिट्टी का प्रकार: अवर जलोढ़ या दोमट मिट्टी

भारत और कदन्न:

- विश्व का सबसे बड़ा कदन्न उत्पादक:
 - वैश्विक उत्पादन का 20%, एशिया के उत्पादन का 80%
- सामान्य कदन्न:
 - रागी (Finger millet), ज्वार (Sorghum), समा (Little millet), बाजरा (Pearl millet), और चेना /पुनर्वा (Proso millet)
 - स्वदेशी किस्में (छोटे बाजरा)-कोदो, कुटकी, चेना और साँवा
- शीर्ष कदन्न उत्पादक राज्य:
 - राजस्थान > कर्नाटक > महाराष्ट्र > मध्य प्रदेश > उत्तर प्रदेश
- सरकार की पहलें:
 - 'गहन कदन्न संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' (INSIMP)
 - इंडियाज वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ
 - मिलेट्स स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज
 - कदन्न के लिये एमएसपी में वृद्धि
 - कृषि मंत्रालय ने 2018 में कदन्न को "पोषक अनाज" के रूप में घोषित किया



**अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष
वर्ष 2023**

भारत द्वारा प्रस्तावित, UNGA द्वारा घोषित

MILLET MAP OF INDIA



महत्त्व

- कम महंगा, पोषण की दृष्टि से बेहतर
- उच्च प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स
- जीवनशैली की समस्याओं और स्वास्थ्य (मोटापा, मधुमेह आदि) से निपटने में मददगार
- फोटो-असवेदनशील, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला, जल गहन

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

प्रलिमिंस के लिये:

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान नधि (पीएम-कृषि), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

मेन्स के लिये:

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लाभ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना संबंधी मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

अधिकांश अर्थशास्त्री सभी कृषि सब्सिडी को प्रत्यक्ष आय सहायता अर्थात् किसानों को **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** में बदलने की वकालत करते हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना:

- **उद्देश्य:** इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परकिलपति किया गया है।
- **कार्यान्वयन:** इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मशिन के रूप में शुरू किया गया था।
 - महालेखाकार कार्यालय की **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के पुराने संस्करण यानी 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम' को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।
- **DBT के घटक:** प्रत्यक्ष लाभ योजना के कार्यान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; **RBI, NPCI**, सार्वजनिक और नजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की नपिटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।
- **DBT के तहत योजनाएँ:** DBT के तहत 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएँ हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं:
 - **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान, स्वच्छ भारत मशिन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आयुष मशिन।**
- **आधार अनिवार्य नहीं:** DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूँकि आधार वशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

DBT के लाभ:

- **सेवाओं के कवरेज का वसितार:** एक मशिन-मोड दृष्टिकोण में, इसने सभी परिवारों के लिये बैंक खाते खोलने, सभी के लिये **आधार** का वसितार करने और बैंकिंग तथा दूरसंचार सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया।
- **तत्काल और आसान मनी ट्रांसफर:** इसने आधार पेमेंट ब्रजि बनाया ताकि सरकार से लोगों के बैंक खातों में तत्काल धन हस्तांतरण किया जा सके।
 - इस दृष्टिकोण ने न केवल सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी प्राप्त करने के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वशिष्ट रूप से जोड़ने की अनुमति दी, बल्कि आसानी से धन भी हस्तांतरित किया।
- **वित्तीय सहायता:** ग्रामीण भारत में, DBT ने सरकार को कम लेन-देन लागत वाले किसानों को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी है।
- **वित्त का हस्तांतरण और सामाजिक सुरक्षा:** शहरी भारत में, **PM आवास योजना** और **LPG पहल योजना** पात्र लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने के लिये DBT का सफलतापूर्वक उपयोग करती है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ और **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये DBT आर्कटिकचर का उपयोग करते हैं।
- **नए अवसरों का द्वार:** **मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिये स्वरोजगार योजना (Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers- SRMS)** जैसे पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत DBT नए अवसर प्रदान करता है जो समाज के सभी वर्गों की सामाजिक गतिशीलता को सक्षम बनाता है।

DBT से संबंधित चुनौतियाँ:

- **अभिम्यता का अभाव:** नामांकन करने का प्रयास करने वाले नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक नामांकन केंद्रों तक पहुँच/निकटता की कमी, अनुपलब्धता, या नामांकन के लिये ज़िम्मेदार अधिकारियों/संचालकों की अनियमित उपलब्धता आदि है।
- **सुविधाओं की कमी:** अभी भी कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र हैं, जिनमें बैंकिंग सुविधा एवं सड़क संपर्क नहीं है। **वित्तीय साक्षरता** की भी आवश्यकता है जो लोगों में जागरूकता बढ़ाएगी।
- **अनशिचितताएँ:** आवेदनों को स्वीकार करने और आगे बढ़ाने में देरी जैसी समस्या है। आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और उसमें पाई गई त्रुटियों/समस्याओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- **प्रक्रिया में व्यवधान:** DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में धन प्राप्त करने के संदर्भ में सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक भुगतान कार्यक्रम में व्यवधान है।
 - व्यवधान के कारण आधार वविरण में वर्तनी की त्रुटियाँ, लंबित KYC, बंद या नष्क्रिय बैंक खाते, आधार और बैंक खाते के वविरण में बेमेल आदि हो सकते हैं।
- **लाभार्थियों की कमी:** **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)**, तेलंगाना सरकार के रायथु बंधु और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर रायथु भरोसा सहित विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाएँ पटाईदार किसानों तक नहीं पहुँचती हैं, यानी पट्टे की भूमि पर खेती करने वालों तक नहीं पहुँचती हैं।

आगे की राह

- **नवोन्मेष का व्यवसथितकरण:** नवोन्मेष प्रणाली को सशक्त बनाना कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर नरितर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
 - यह भारत की आबादी की वविधि ज़रूरतों को पूरा करने और संतुलित, न्यायसंगत तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **उपलब्धता:** वशिष्ट रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं में नागरिकों के लिये नामांकन केंद्रों तक पहुँच बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।
- **सभी के लिये एक सामान्य नकिया:** लाभार्थियों को उनके मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिये सभी स्तरों- राज्य, ज़िला और ब्लॉक में सभी DBT योजनाओं के लिये एक सामान्य शकियात नविरण प्रकोष्ठ की स्थापना।
- **पट्टे पर देना (लीजिंग):** जैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन है अथवा वे जिनोंने पट्टे पर ले रखा है, को समेकित जोत पर संचालन करने में मदद कर सकता है, साथ ही मालिकों को अपनी भूमि के नुकसान संबंधी ज़ोखमि के बिना गैर-कृषि रोजगार में भी मदद करता है।

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतशील कदम है, कनितु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टपिपणी कीजयि। (2022)

सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस

एशयिा में जलवायु स्थति, 2021

प्रलिमिंस के लयि:

एशयिा में वर्ष 2021 में जलवायु की स्थति, वशि्व मौसम वजिज्ञान संगठन, ESCAP, आकस्मकि बाढ, चक्रवात, समुदर के स्तर में वृद्धि, ला नीना, मैंग्रोव

मेन्स के लयि:

बढती आपदा से संबंघति मुद्दे और आवश्यक कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वशि्व मौसम वजिज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) और एशयिा एवं प्रशांत के लयि संयुक्त राष्ट्र आर्थकि व सामाजकि आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) द्वारा एशयिा में जलवायु की स्थति 2021 रिपोरट प्रकाशति की गई थी।

रिपोरट के नषिकरष:

- वर्ष 2021 में एशयिा में होने वाली प्राकृतकि आपदाओं में बाढ और चक्रवात 80% का योगदान था।
 - प्राकृतकि आपदाओं के कारण वर्ष 2021 में एशयिाई देशों को 35.6 बलियिन अमेरकि डॉलर का वत्तीय नुकसान हुआ। बाढ "मानवीय और आर्थकि क्षति के मामले में एशयिा में अब तक की सबसे ज़यादा प्रभावशाली" घटना थी।
 - इससे पता चला कि ऐसी आपदाओं का आर्थकि प्रभाव पछिले 20 वर्षों के औसत की तुलना में अधिक है।
- भारत को बाढ के कारण कुल 3.2 बलियिन अमेरकि डॉलर का नुकसान हुआ और देश को जून तथा सतिंबर 2021 के बीच मानसून के मौसम में भारी वर्षा और फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ) का सामना करना पड़ा।
 - इन घटनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 1,300 लोग मारे गए और इससे फसलों और संपत्तियों को नुकसान पहुँचा।
 - इस संबंघ भारत एशयिाई महाद्वीप में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था।
- इसी तरह चक्रवातों से भी काफी आर्थकि क्षति हुई जिसमें सबसे ज़यादा क्षति भारत (4.4 बलियिन अमेरकि डॉलर) को हुई और इसके बाद चीन (3 बलियिन अमेरकि डॉलर) और जापान (2 बलियिन अमेरकि डॉलर) का स्थान है।
- इसके अतरकि, 2021 में, देश के वभिन्नि हसिंसों में आँधी और आकाशीय बजिली से लगभग 800 लोगों की जान चली गई।
 - वर्ष 2021 के दौरान भारत में ≥ 34 समुदरी मील की अधिकतम वायु की गति वाले पाँच चक्रवातों (ताउते, यास, गुलाब, शाहीन, जवाद) ने भारत को प्रभावति कयि।
 - इसके अतरकि वर्ष 2021 में देश के वभिन्नि हसिंसों में आँधी और आकाशीय बजिली से लगभग 800 लोगों की जान गई थी।
- अरब सागर और क्युरोशयिो धारा का तेज़ी से गर्म होना:
 - अरब सागर और क्युरोशयिो धारा के तेज़ी से गर्म होने के कारण, ये क्षेत्र औसत वैश्वकि समुदरी सतही तापमान की तुलना में तीन गुना तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।
 - महासागर के गर्म होने से समुदर का जल स्तर बढ़ सकता है चक्रवात की दशिा और महासागर की धाराओं का पैटर्न बदल सकता है।
 - महासागर की ऊपरी सतह का गर्म होना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह संवहन धाराओं, वायु, चक्रवातों आदि के रूप में वातावरण को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावति करता है।
 - महासागर का नतिल, वातावरण को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावति नहीं करता है।
 - अरब सागर इस संदर्भ में अद्वितीय है क्योंकि यह वायुमंडलीय टनल और ब्रजि के माध्यम से अतरकि ऊष्मा को ग्रहण करने का माध्यम है और वभिन्नि महासागरों से मशि्रति गर्म जल भी इसमें आकर मलिता है।
 - लेकनि क्युरोशयिो धारा प्रणाली में उष्णकटबिंधीय जलसतह से गर्म जल ग्रहण करती है और इससे इसका तापमान बढ़ जाता है।
- ला नीना:
 - पछिले दो वर्ष ला नीना से प्रभावति थे और इस दौरान भारत में स्थापति दबाव पैटर्न उत्तर से दक्षिण की ओर शफिट हो जाता है, जो

यूरेशिया और चीन से परसिंचरण को संचालति करता है।

- यह भारत के कुछ हस्सिाँ में अत्यधिक वर्षा पैटर्न का कारण बन सकता है , विशेष रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप में, जहाँ पूर्वोत्तर मानसून आता है। पछिले वर्ष की अधकितता ला नीना दबाव पैटर्न से संबंघति थी।

■ अनुकूलन में नविश:

- जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लयि भारत को वार्षकि 46.3 बलियन अमरीकी डॉलर का नविश करने की आवश्यकता होगी (जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% है)।

- आम तौर पर **GDP की तुलना अनुकूलन में नविश करने के लयि कसिी देश की क्षमता को दर्शाती है।**

- कुछ अनुकूलन प्राथमकितार्णें जनिके लयि उच्च नविश की आवश्यकता होती है, उनमें लचीला बुनयिादी ढाँचा, शुषक भूमि कृषि में सुधार, लचीली जल बुनयिादी ढाँचा, बहु-जोखमि प्रारंभकि चेतावनी प्रणाली और प्रकृत-आधारति समाधान शामिल हैं।
- भारत के तटीय राज्यों के लयि, जहाँ चक्रवात के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, प्रकृत-आधारति समाधान महत्वपूर्ण हैं जैसे मैंग्रोव की रक्षा से चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में मदद मलि सकती है।

■ अनुकूलन नधि:

- भारत के पास अलग से अनुकूलन नधि नहीं है, लेकिन यह वतित कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण क्षेत्रों की कई योजनाओं में अंतरनहिति है।
- उदाहरण के लयि, [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना](#) जैसी प्रमुख परयोजनाओं, जनिका वर्ष 2020 में 13 बलियन अमरीकी डॉलर का वार्षकि बजट था, को आपदा-प्रवण क्षेत्रों में अनुकूलन को संबोधति करना चाहयि।
 - इसके बजट का लगभग **70% प्राकृतकि संसाधन प्रबंधन में जाने और लचीले बुनयिादी ढाँचे के नरिमाण के लयि चहिनति कयिा गया है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. उच्च तीव्रता वाली वर्षा के कारण शहरी बाढ़ की आवृत्तविर्षों से बढ़ रही है। शहरी बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए ऐसी घटनाओं के दौरान जोखमि को कम करने की तैयारी के तंत्र पर प्रकाश डालयि। (2016)

प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्वकि समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावति होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावति होंगे? (2017)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

नई चेतना-पहल बदलाव की

प्रलिमिस के लयि:

नई चेतना अभयान, कुदुम्बशरी मशिन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा

मेन्स के लयि:

नई चेतना अभयान, कुदुम्बशरी मशिन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा, लगी आधारति हसिा के कारण, लगी आधारति हसिा को समाप्त करने के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शहरी वकिसा मंत्रालय ने "नई चेतना-पहल बदलाव की" लगी आधारति भेदभाव के खलिाफ समुदाय-नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभयान शुरू कयिा है।

- केरल ने भी इसी प्रकार की पहल कुदुम्बशरी मशिन के तहत अभयान शुरू कयिा।

नई चेतना-पहल बदलाव की, अभयान

परचिय:

- यह चार सप्ताह का अभयान है, जसिका उद्देश्य महिलाओं को हसिा को पहचानने और रोकने एवं उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लयि तैयार करना है।

- गतविधियिाँ '[लैंगकि समानता](#) और लगी आधारति हसिा' के वषिय पर केंद्रति होंगी।

लक्ष्य:

- यह एक वार्षिक अभियान होगा जो प्रत्येक वर्ष वशिष्ट लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस वर्ष अभियान का लक्ष्य **आधारति हिसा** है।

कार्यान्वयन एजेंसी:

- यह अभियान सभी राज्यों द्वारा **नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisations- CSO)** के भागीदारों के सहयोग से लागू किया जाएगा और **राज्यों, जिलों एवं ब्लॉकों सहित सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जाएगा**, जिसमें वसितारति समुदाय के साथ सामुदायिक संस्थानों को शामिल किया जाएगा।।

महत्त्व:

- अभियान हिसा के मुद्दों को **स्वीकार करने, पहचानने और संबोधित करने हेतु ठोस प्रयास करने के लिये सभी संबंधित विभागों एवं हतिधारकों को एक साथ लाएगा।**

कुदुम्बशरी मशिन

- यह केरल सरकार के राज्य **गरीबी उन्मूलन मशिन (State Poverty Eradication Mission- SPEM)** द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।
- मलयालम भाषा में कुदुम्बशरी नाम का अर्थ है 'परिवार की समृद्धि'। यह नाम 'कुदुम्बशरी मशिन' या SPEM के साथ-साथ कुदुम्बशरी सामुदायिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन



परचिय:

- इसे "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission- DAY-NRLM)" के रूप में जाना जाता है।
- यह जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया **केंद्र प्रायोजति कार्यक्रम** है।
- सरकार ने प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की सफिराशि को स्वीकार कर वतित वर्ष 2010-11 में "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)" को "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन (NRLM)" में पुनर्गठित किया।

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वतितिय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

उप- योजनाएँ

महिला कसिन सशक्तीकरण परयोजना:

- कृषि-पारसिथितिकि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये जो महिला कसिनों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी इनपुट लागत और जोखिम को कम करते हैं, यह मशिन महिला कसिन सशक्तीकरण परयोजना (MKSP) को लागू कर रहा है।।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमति कार्यक्रम और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना:

- यह अपनी गैर-कृषि आजीविका रणनीति के भाग के रूप में **DAY-NRLM स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमति कार्यक्रम (SVEP)** और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) कार्यान्वित कर रहा है।
 - SVEP का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों की स्थापना के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।
 - AGEY को अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, जो दूरदराज के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक नगिरानी वाली ग्रामीण परविहन सेवाएँ प्रदान करता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:

- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY)** का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़े कौशल का निर्माण

करना और उन्हें अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च मजदूरी वाले रोजगार क्षेत्रों में रखना है।

● **ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान:**

- 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार लेने के लिये कुशल बनाने के लिये **ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों (RSETIs)** को सहायता प्रदान कर रहा है।

लगि आधारति हसिा के प्रमुख कारण:

■ **सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक कारण:**

- भेदभावपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मानदंड और प्रथाएँ महिलाओं और लड़कियों को हाशिए पर डालती हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करने में वफिल रहती हैं।
- लैंगिक रूढ़ियों का उपयोग अक्सर महिलाओं के खिलाफ हसिा को सही ठहराने के लिये किया जाता है। सांस्कृतिक मानदंड अक्सर यह तय करते हैं कि पुरुष आक्रामक, नयितरति और प्रमुख हैं, जबकि महिलाएँ वनिमर, अधीन हैं, और प्रदाताओं के रूप में पुरुषों पर भरोसा करती हैं। ये मानदंड दुरुपयोग की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं।
- परिवार, सामाजिक और सांप्रदायिक संरचनाओं का पतन और परिवार के भीतर बाधति भूमिकाएँ अक्सर महिलाओं और लड़कियों को जोखिम में डालती हैं और सुरक्षा और नविवरण के लिये तंत्र और अवसरों को सीमति करती हैं।

■ **व्यक्तगत बाधाएँ:**

- सामाजिक कलंक, अलगाव और सामाजिक बहिष्कार का खतरा या डर तथा आने वाले समय में अपराधी, समुदाय, या अधिकारियों के हाथों गरिफ्तारी, हरिसत में लयि जाना, दुरुव्यवहार और सज़ा हसिा का शकिार होने की धमकी या डर शामिल है।
- **मानवाधिकारों** के बारे में जानकारी का अभाव।

महिलाओं के खिलाफ हसिा के प्रभाव:

- यह महिलाओं के स्वास्थय के सभी पहलुओं-शारीरिक, यौन और प्रजनन, मानसिक और व्यावहारिक स्वास्थय को गंभीर रूप से प्रभावति करता है। इस प्रकार यह उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से वंचति करता है।
- हसिा और संबंधति धमकी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के कई रूपों में सक्रयि तथा समान रूप से भाग लेने की क्षमता को प्रभावति करती है।
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न और घरेलू हसिा का कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर प्रभाव पड़ता है।
- यौन उत्पीड़न महिलाओं के शैक्षिक अवसरों और उपलब्धियों को सीमति करता है।

लगि आधारति हसिा को खत्म करने के लयि आवश्यक कदम:

- लगि आधारति हसिा (Gender Based Violence- GBV) को समाज, सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से समाप्त किया जा सकता है।
- लगि आधारति हसिा को पहचानने और पीड़ितों की पहचान कर उससे संबंधति आवश्यक कदम उठाने के लयि स्वास्थय सेवा प्रदाताओं को प्रशक्षति करना पीड़ितों की सहायता करने के सबसे महत्त्वपूर्ण तरीकों में से एक है।
- GBV को दृश्यमान बनाने, वजिापन समाधानों, नीति-नरिमाताओं को सूचति करने और जनता को कानूनी अधिकारों के बारे में शक्षति करने और GBV को पहचानने और इसे रोकने के लयि मीडयिा एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
- **शक्षिा:** स्कूल, GBV को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं। नयिमति पाठ्यक्रम, यौन शक्षिा, स्कूल परामर्श कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थय सेवाओं द्वारा हसिा को रोका जा सकता है।
- कई अध्ययनों से पता चला है कि GBV को रोकने के लयि इसकी पहचान, समाधान और संबंधति कार्यप्रणाली में सभी समुदायों को शामिल करना इसे रोकने के बेहतर तरीकों में से एक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कृकृतय के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से नपिटने के लयि कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। (2014)

सरोत: द हदि

चौथा भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद

प्रलम्बिस के लयि:

चौथा भारत-फ़र्रांस वार्षकिक रकषा संवाद, भारत-फ़र्रांस सैन्य अभ्यास, अंतर्राष्टरीय सौर गठबंधन ।

मेन्स के लयि:

भारत के हतियों पर वकिसति तथा वकिसशील देशों की नीतयियों तथा राजनीतिका प्रभाव, भारत-फ़र्रांस संबंध

चर्चा में क्यो?

हाल ही में चौथी भारत-फ़र्रांस रकषा वारता, भारत में आयोजति की गई ।



प्रमुख बदि:

- रकषा औद्योगकिक सहयोग:
 - दोनों ही देशों ने 'मेक इन इंडिया' पर बल देने के साथ रकषा औद्योगकिक सहयोग पर चर्चा की ।
 - इस वारता के दौरान द्वपिकषीय, कषेत्रीय और रकषा औद्योगकिक सहयोग के मुद्दों पर वसितृत चर्चा की गई ।
- सैन्य सहयोग:
 - दोनों देशों ने भावी सैन्य सहयोग की समीक्षा की, जसिमें हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है ।
 - इन्होंने कई "रणनीतकिक मुद्दों और हदि-प्रशांत कषेत्र पर ध्यान देने के साथ द्वपिकषीय, कषेत्रीय तथा बहुपकषीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने हेतु एक साथ काम करने की प्रतबिद्धता दखिआई ।
- हदि महासागर कषेत्र:
 - इस वारता के दौरान IOR (हदि महासागर कषेत्र) में समुद्री चुनौतयियों के आलोक में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई ।
 - फ़र्रांस ने हदि-प्रशांत कषेत्र में अपनी भागीदारी सुनश्चिति करने और इस कषेत्र में फ़र्रांसीसी रणनीतकिक संदर्भ में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला ।
 - फ़र्रांस, हदि महासागर आयोग (IOC) और हदि महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) का वर्तमान अध्यक्ष है और दोनों ही देश इन मंचों पर सहयोगी भूमिका में हैं ।

भारत-फ़र्रांस सामरकिक संबंध:

- पृष्ठभूमि:
 - जनवरी 1998 में शीत युद्ध की समाप्तिके बाद फ़र्रांस उन पहले देशों में से एक था जसिके साथ भारत ने 'रणनीतकिक साझेदारी' पर हस्ताक्षर कयि थे ।
 - वर्ष 1998 में परमाणु हथयारों के परीक्षण के भारत के फैसले का समर्थन करने वाले बहुत कम देशों में से फ़र्रांस एक था ।
- रकषा सहयोग: दोनों देशों के बीच मंत्रसितरीय रकषा वारता आयोजति की जाती है ।
 - तीनों सेनाओं द्वारा नयिमति समयांतराल पर रकषा अभ्यास कयिा जाता है; अर्थात्
 - अभ्यास शकत (स्थल सेना)
 - अभ्यास वरण (नौसेना)
 - अभ्यास गरुड (वायु सेना)
 - हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) में फ़र्रेंच राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू वमिन को शामिल कयिा गया है ।
 - भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगकिकि-हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से भारत के मझगाँव डॉकयार्ड में छह स्कॉर्पीन पनडुबयियों के नरिमाण के लयि एक फ़र्रांसीसी कंपनी के साथ अनुबंध कयिा ।
 - दोनों देशों ने पारस्परकिक 'लॉजसिटकिस सपोर्ट एग्रीमेंट' (Logistics Support Agreement- LSA) के प्रावधान के संबंध में

समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

- यह समझौता नयिमति पोर्ट कॉल के साथ-साथ **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)** के अंतर्गत अन्य देशों के युद्धपोतों, सैन्य वमिनो एवं सैनिकों के लिये ईंधन, राशन, उपकरणों रखरखाव तथा आपूर्ति की सुविधा में मदद करेगा।

■ हृदय महासागर क्षेत्र: साझा सामरिक हति:

- फ्रांस को अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति जैसे- रीयूनियन द्वीप और हृदय महासागर के भारतीय क्षेत्र पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की रक्षा करने की आवश्यकता है।
- हाल ही में फ्रांस **हृदय महासागर रमि एसोसिएशन (IORA) का 23वाँ सदस्य** बन गया है।
 - यह पहली बार है कि कोई ऐसा देश जिसकी मुख्य भूमि हृदय महासागर में नहीं है और उसे IORA की सदस्यता प्रदान की गई है।
- **आतंकवाद वरिधी:** फ्रांस ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन के लिये भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। दोनों देश एक नए 'मनी फॉर टेरर' - **फाइटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग** पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का भी समर्थन करते हैं।
- **फ्रांस द्वारा भारत का समर्थन:** फ्रांस भी कश्मीर को लेकर भारत का लगातार समर्थन कर रहा है जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में हाल के दिनों में कमी देखी गई है और चीन का दृष्टिकोण संदेहास्पद रहा है।

■ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध:

- **भारत-फ्रांस प्रशासनिक आर्थिक और व्यापार समिति (India-France Administrative Economic and Trade Committee- AETC)** द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को और बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक ऑपरेटर्स के लाभ के लिये बाजार पहुँच के मुद्दों के समाधान को गति देने के तरीकों का आकलन करने एवं खोजने हेतु एक उपयुक्त ढाँचा प्रदान करती है।
- **अप्रैल 2000 से जून 2022 तक 10.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के संचयी निवेश के साथ फ्रांस भारत में 11वाँ सबसे बड़ा वदेशी निवेशक है, जो **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT)** द्वारा प्रदान किये गए आँकड़ों के अनुसार भारत में कुल FDI प्रवाह का 1.70% है।
- फ्रांस के भारत को होने वाले कुल निर्यात में एयरोनॉटिक्स की हस्सेदारी 50% है। भारत से फ्रांसीसी आयात में **भ्रसाल-दर-साल 39% (2019 की तुलना में 7%) की वृद्धि हुई है।**

■ वैश्विक एजेंडा:

- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, नवीकरणीय ऊर्जा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी, आदि:
- जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को वकिसति करने के लिये संयुक्त प्रयास किये गए हैं।
- दोनों देश साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक रोड मैप पर सहमत हुए हैं।

■ अंतरिक्ष:

- फ्रांस ने वर्ष 2025 के लिये निर्धारित भारत के वीनस मशिन का हस्सिसा बनने पर सहमत व्यक्त की है।
- ISRO के वीनस उपकरण, VIRAL (Venus Infrared Atmospheric Gases Linker) को रूसी और फ्रांसीसी एजेंसियों द्वारा सह-वकिसति किया गया है।

आगे की राह:

- फ्रांस, जिसने अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के ढाँचे के भीतर रणनीतिक स्वायत्तता की मांग की थी और भारत, जिसने स्वतंत्र वदेश नीतिको महत्त्व दिया है, अनश्चित काल के लिये नए गठबंधन के निर्माण में स्वाभाविक भागीदार हैं।
- फ्रांस वैश्विक मुद्दों पर यूरोप के साथ गहरे जुड़ाव का मार्ग भी खोलता है, विशेषकर **बरेकजिट (BREXIT)** के कारण इस क्षेत्र में अनश्चितता के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई।
- यह संभावना व्यक्त की गई कि फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव के लिये कहीं अधिक परिणामी साबित होगी।

स्रोत: द हिंदू